निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) "नगर विकास" के विस्तृत कार्यक्रमों का बनाना राज्य क्षेत्र में है। "नगर विकास" परियोजनाओं को बनाने तथा मंजूर करने में राज्य सरकारें सक्षम हैं। निर्माण तथा आवास मंत्रालय के पास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल नगर के लिए बनाई गई विकास योजना का कोई ब्यौरा नहीं है।

मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना

1491. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) सरकार ने मध्य प्रदेश में कोरवा नामक स्थान पर कोयले पर आधारित एक उर्वरक सन्यन्त्र की स्थापना का अनुमोदन किया है, जिसकी यूरिया के रूप में 1,229,000 मीटरी टन नाइट्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता होगी। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि इस प्रायोजना को ठीक समय में कब कार्यान्वित किया जायेगा क्योंकि इसके कार्यक्रम के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है।

Eastern Headquarter of Oil and Natural Gas Commission without General Manager

1492. SHRI BISWANARAYAN SHASTRI: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether the eastern headquarter of Oil and Natural Gas Commission is without a General Manager for months together ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether it is hampering the proper working of the Commission ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI P. C. SETHI) : (a) and (b) : The post of General Manager, Eastern Region, Oil and Natural Gas Commission, at Nazira (Assam) fell vacant on April 19, 1970, due to retirement of the incumbent. The efforts of the Commission, since then, to find a suitable person to man this post substantively, have not succeeded as yet, and are still continuing.

(c) No, Sir. To avoid any dislocation of work, the Commission have appointed senior officers to officiate in the post and to attend to its duties, till a substantive appointment to this post was made.

Removing of Rigs from Shivasagar district without drilling

1493. SHRI BISWANARAYAN SHASTRI: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether recently in Eastern Region, Oil and Natural Gas Commission had prepared some ground in five places in Shivasagar district and fixed rigs and subsequently removed them without drilling ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI P. C. SETHI) : (a) No Sir. There has been no case in the recent past where Oil and Natural Gas Commission in their Eastern Region have moved a Rig out of drill-site without drilling the well.

(b) Does not arise.

नगरों तथा गांवों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए मकान

1494. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरों में कितने व्यक्ति आवास की पर्याप्त व्यवस्था के बिना रह रहे हैं ;

(ख) गांवों में कितने व्यक्ति आवास की पर्याप्त सुविधाओं के बिना रह रहे हैं ;

(ग) उपयुक्त मकानों के बिना रहने वाले व्यक्तियों के लिए सस्ते मकानों तथा न्यूनतम सुविधाओं की कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी; और

(घ) आगामी 5 वर्षों में वर्षवार ऐसे कितने मकानों का निर्माण किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) इस बारे में फिलहाल कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1971 की जनगणना में इस बारे में एकत्रित किए गए ब्यौरे की जांच में काफी समय लगेगा। तथापि, चौथी योजना (1969-74) के लिए आवास पर कार्यकारी दल ने, योजना के आरम्भ में देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की क्रमशः 119 लाख और 718 लाख एककों की कुल कमी का अनुमान लगाया था। ये आंकड़े इस मान्यता पर आधारित थे, कि प्रत्येक परिवार के पास उचित प्रकार का एक पक्का रहने योग्य रिहायशी एकक होना चाहिए तथा तदनुसार इसमें कच्चे तथा जीर्णावस्था के वे मकान शामिल हैं, जिनका बदला जाना अथवा पर्याप्त सुधार करना अपेक्षित है।

(ग) उपलब्ध सीमित साधनों, उन साधनों पर मांगों की प्राथमिकताओं तथा समस्या की विशालता को देखते हुए, इसके समाधान के लिए समय की कोई सीमा नहीं बताई जा सकती।

(घ) सामाजिक आवास और नगर-विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 195.27 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है। इस लागत से चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, लगभग 2,00,000 मकानों के निर्माण किए जाने की आशा है।

बिहार में कुष्ठ रोगियों को राहत देने के लिए सहायता

1495. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार में कुष्ठ रोगियों की संख्या 2.8 लाख है जब कि राज्य कुष्ठ रोगी प्राधिकरण द्वारा हाल ही में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में उनकी संख्या 6.1 लाख है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य प्राधिकरण द्वारा किए गए सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए कुष्ठ रोगियों को राहत देने हेतु सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचनानुसार, बिहार में कुष्ठ रोगियों की संख्या 2.8 लाख है। यह संख्या 1963 में उपलब्ध मुख-विज्ञान (एपिडिमियोलाजिकल) आंकड़ों पर आधारित है। फिर भी राज्य सरकार के राज्य कुष्ठ अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कुष्ठ रोगियों की संख्या 6.1 लाख है।

(ख) 1955 में बिहार में चलाए गए राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के ढांचे के अन्तर्गत, घर-घर जाकर इलाज करने वाली चलती फिरती गाड़ी के आधार पर कुष्ठ रोगियों को चिकित्सीय राहत मुहैय्या करने के लिए पहले ही 22 कुष्ठ नियन्त्रण एककों तथा 10 सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, कुष्ठ क्षेत्र में इस काम के लिए तीन स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान भी दिया जा रहा है। अब तक 25 लाख लोग इसके अन्तर्गत आ गए हैं और राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के उपर्युक्त तीनों संगठनों द्वारा 65679 मामले दर्ज किए गए है।